भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या 1632

सोमवार, 01 अगस्त, 2022 (श्रावण 10, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>तमिलनाडु के तंजावूर में नया विमानपत्तन</u>

1632. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु के तंजावूर जिले में एक नया विमानपत्तन बनाने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके लिए कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))</u>

(क) से (ग): भारत सरकार ने ग्रीनफ़ील्ड विमानपत्तन (जीएफ़ए) नीति, 2008 तैयार की है, जिसमें देश भर में ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों के निर्माण से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश, प्रक्रियाओं और विभिन्न चरणों का विवरण दिया गया है। जीएफ़ए नीति के अंतर्गत, परियोजना प्रस्तावक - कोई हवाईअड्डा विकासकर्ता अथवा संबंधित राज्य सरकार, जो ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डा स्थापित करने को इच्छुक हैं, के लिए आवश्यक है कि वह दो चरण प्रक्रिया, अर्थात 'साइट मंजूरी' तथा उसके बाद 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए www.civilaviation.gov.in पर उपलब्ध नियत प्रारूप में, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को प्रस्ताव भेजे। ऐसे प्रस्तावों पर, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा, जीएफ़ए नीति में नियत प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। जीएफ़ए नीति के अनुसार, तंजावूर, तमिलनाडु में ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु, नागर विमानन मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तंजावूर में एक हवाईअड्डा मौजूद है, जो भारतीय वायुसेना (आईएएफ़) के अंतर्गत है। तंजावूर हवाईअड्डे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) 26.5 एकड़ भूमि का स्वामी है। तथापि, उक्त भूमि हवाईअड्डे के परिचालन हेतु सभी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, एएआई एवं आईएएफ़ ने तंजावूर में नए सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु भूमि के आपसी आदान-प्रदान के लिए सहमति दी है।

देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने तथा आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने हेतु, नागर विमानन मंत्रालय ने अक्तूबर, 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की। तंजावूर में मौजूदा हवाईअड्डे को स्तरोन्नयन/विकास एवं वहाँ से आरसीएस उड़ानों के प्रचालन हेतु आरसीएस योजना के तहत बोली प्रक्रिया के दूसरे दौर में चिन्हित किया गया है।